सीएमडी, इरेडा ने "भारत के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए वित्तपोषण" पर पैनल चर्चा में भाग लिया

इरेडा को अगले पांच वर्षों में पांच गुना वृद्धि की उम्मीद और तीसरी तिमाही में आईपीओ की योजना

नई दिल्ली, 16 जुलाई 2021

इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), श्री प्रदीप कुमार दास ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित अक्षय ऊर्जा विनिर्माण के लिए डिजिटल सम्मेलन के दूसरे संस्करण और "आत्मनिर्भर भारत- आत्मनिर्भरता" पर प्रदर्शनी के दौरान "भारत के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए वित्तपोषण" पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया।

श्री दास ने दोहराया कि इरेडा केवल लाभ अर्जित करने का प्रयास ही नहीं करता है, बल्कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से वित्त पोषण और अन्य माध्यमों से आरई विकास के लिए मातृत्व संगठन के रूप में आरई क्षेत्र के व्यापक हित में काम करता है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आरई परियोजनाओं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परियोजना के लागत को कम करके किया जा सकता है। इसे संचालन, रखरखाव और वित्त लागत को कम करके प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए इरेडा आरई परियोजनाओं के लिए बहुत ही आकर्षक दर पर वित्त पोषण कर रहा है। कंपनी मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुरूप अपनी उधार दरों को लगातार कम कर रही है।

श्री दास ने दोहराया कि इरेडा केवल लाभ कमाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से वित्त पोषण और अन्य माध्यमों के माध्यम से आरई विकास के लिए मुख्य संगठन के रूप में आरई क्षेत्र के व्यापक हित में काम करता है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आरई परियोजनाओं के अस्तित्व को परियोजना लागत को कम करके

संचालित किया जा सकता है। इसे संचालन, रखरखाव और वित्त लागत को कम करके प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए इरेडा आरई परियोजनाओं को बहुत ही आकर्षक दर पर वित्त पोषण कर रहा है। कंपनी मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुरूप अपनी उधार दरों को लगातार कम कर रही है।

'व्यवसाय करने में आसानी' के एक भाग के रूप में, इरेडा ने मंजूरी, संवितरण, और दस्तावेज़ीकरण आदि के लिए प्रोसेसिंग समय में लगभग 30% की कमी के संबंध में सफलता हासिल की है। हाल के दिनों में, इरेडा ने उधारकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से इरेडा कार्यालय आए बिना तीन ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। । इन पहलों के साथ, कई डेवलपर जिन्होंने पहले उच्च ब्याज दरों के कारण अपनी परियोजनाओं को चालू करने के बाद अपने ऋणों का पूर्व भुगतान करके इरेडा से ऋण लेना छोड़ दिया था, अब आकर्षक ब्याज दरों के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी और सुशासन के कारण इरेडा के पास वापस आ रहे हैं।

श्री दास ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एमएनआरई की नोडल एजेंसी के रूप में इरेडा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे 12,000 मेगावाट सीपीएसयू स्टेज - II सौर परियोजना योजना और सौर विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4,500 करोड़ रुपये की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। पीएलआई योजना के लाभार्थियों का चयन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा और बोलियों का मूल्यांकन कंपनियों द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित विनिर्माण क्षमता और भारत में सौर पैनलों के निर्माण के लिए आवश्यक प्राथमिक उत्पादों के आधार पर किया जाएगा।

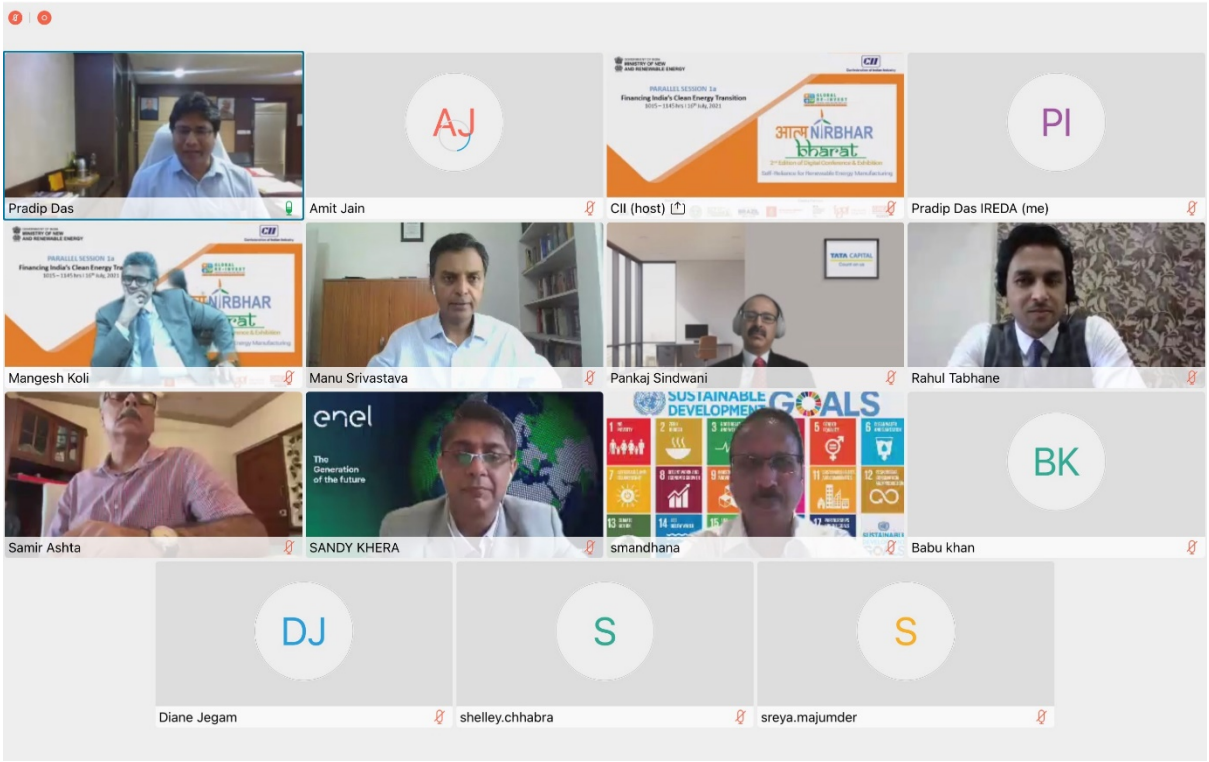

अगले पांच वर्षों के लिए कंपनी और आरई क्षेत्र की भविष्य की योजनाओं पर बोलते हुए, श्री दास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इरेडा को उम्मीद है कि आरई क्षेत्र में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के वित्तपोषण के साथ, वित्तीय वर्ष 2026 तक, इसकी ऋण बुक में 28000 करोड़ रुपये (लगभग) से 1,35,000 करोड़ (लगभग) रुपये की बढ़ोत्तरी होगी । कंपनी वित्तीय वर्ष 2026 तक एनबीएफसी द्वारा आरई सेक्टर के ऋण फंडिंग का 40% से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य बना रही है। वर्तमान में, इरेडा के पास देश में कुल स्थापित आरई क्षमता का 19% (लगभग) वित्तपोषण का बाजार का हिस्सा है। श्री दास ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इरेडा को सितंबर-अक्टूबर 2021 तक 1500 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है, जिसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2021-22 के दौरान की थी। तदनुसार, इरेडा नवंबर-दिसंबर 2021 के तीसरी तिमाही में अपना आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

वितरण क्षेत्र योजना के सुधारों पर अपने विचार साझा करते हुए, सीएमडी, इरेडा ने रेखांकित किया कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्य उपयोगिताओं/डिस्कॉमों द्वारा सामना किए जा रहे समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम कर रही है। हाल ही में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) सुधार योजना के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये की मार्की को मंजूरी दी, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 97,631 करोड़ रुपये होगी ।

इसके अलावा, श्री दास ने इस बात पर जोर दिया कि बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के ताने-बाने में विश्वास कारक जैसे कि बिजली खरीद समझौते (पीपीए) का सम्मान करना, भुगतान सुरक्षा प्रणाली आदि के अनुरूप समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है, जिसके लिए सभी हितधारकों (डेवलपर्स, ऋणदाताओं, बिजली उपयोगिताओं, डिस्कॉम, उपभोक्ताओं, आदि) को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे आना होगा।

अपने संबोधन को समाप्त करते हुए, श्री दास ने आग्रह किया कि पेरिस समझौते के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन को 33 प्रतिशत तक कम करने के लिए भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्षय ऊर्जा के प्रदर्शन में तेजी लाने के अवसर का लाभ उठाने का समय आ गया है।